

5.00 P.M.

पार्टी की आलोचना कर रहे थे, तो एक कांग्रेस के सदस्य ने कहा कि आपको मालूम नहीं है कि सुचेता कृपलानी जी कहां पहुंच गई हैं? कृपलानी जी की धर्म पत्नी सुचेता कृपलानी जी कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी थीं। कृपलानी जी समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी में थे। वह आज की समाजवादी पार्टी नहीं थी, वह तब की सोशलिस्ट पार्टी थी। कृपलानी जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग 'stupid fools' हैं, लेकिन वे अपहरण करते हैं, यह मुझे मालूम नहीं था। पूरा सदन हंसी के भाव में गुजर गया। यह सदन का माहौल था। हम उस माहौल से कहां से कहां पहुंच गए। मैं इसका एक दूसरा उदारहण देना चाहता हूँ, मैं डी. राजा जी को सुन रहा था। हमारा संसदीय इतिहास बहुत पुराना नहीं है, यदि हम स्वतंत्र भारत को देखें, तो यह कुछ दशकों का इतिहास है। उस इतिहास में सभी पार्टियों का, सभी विधान सभाओं का, लोक सभा और राज्य सभा का आत्मालोचन करें, तो मैं खासकर के डी. राजा जी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अगर मेरे मित्र बैठे हुए हैं, तो याद दिलाना चाहता हूँ। पश्चिमी बंगाल में यूनाइटेड फ्रंट एक्सपेरिमेंट हुआ था। वह बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था, कांग्रेस के खिलाफ एक्सपेरिमेंट था, बंगला कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआईएम का एक्सपेरिमेंट था। विश्वनाथ मुखर्जी और लहरी दो सीपीआई के नेता थे, जो बंगला कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री अजय मुखर्जी जी के साथ थे, डी. राजा जी को अपना इतिहास याद होगा। श्री ज्योति बाबू डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अजय मुखर्जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच का पत्र व्यवहार आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): सिन्हा जी, ...**(व्यवधान)**... मालूम है। आपका भाषण जारी रहेगा। अगले सत्र में आपका भाषण continue रहेगा। आपकी मेडेन स्पीच थी, लेकिन समय कम है, क्योंकि अभी हमें दूसरा विषय लेना है। अगले सत्र में आप बोलिएगा।

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I have to inform Members that the Business Advisory Committee, in its meeting held on the 3rd of August, 2018, has allotted time for Government Legislative and other Business as follows:-

| Business | Time Allotted |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following Demands for Grants, after they are passed by Lok Sabha:- | Two Hours |
| (a) Supplementary Demands for Grants for 2018-19. | (To be discussed together) |
| (b) Demands for Excess Grants for 2015-16. | |

| Business | Time Allotted |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2. Consideration and passing of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018, after it is passed by Lok Sabha. | Two hours |

2. The Committee also recommended that the House may sit beyond 6.00 p.m., as and when necessary, for the transaction of Government Legislative and other Business.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Special Mentions. Shri D. Raja.

SPECIAL MENTIONS

Urging the Government to direct the CIFRI, Barrackpore to be more pro-active and help save inland fishery resources

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, the Central Inland Fisheries Research Institute at Barrackpore is the nodal agency for all inland fishery resources across the country. However, the CIFRI does not seem to have done any surveys or brought out plans for saving the millions of fishermen who face fast depleting fishery resources in all inland water bodies.

The CIFRI has regional offices all over the country. A number of petitions have been sent to the CIFRI by various concerned people to start surveys and come up with plans to protect fishery resources and the biodiversity in our rivers.

The depletion of river water, tanks and other inland water bodies has caused severe economic problems and depression in fishermen's lives. The CIFRI should take the initiative and set up surveys everywhere, starting with major rivers.

It is learnt that over the last ten years, the CIFRI has not done any major survey or made any major recommendations to the Government on how to protect fishermen who face depleting fishery resources and the impact of dams on fishery resources and fishermen.

If a dam is constructed, it should not harm fishermen's livelihood. There are designs to ensure that there is constant environmental flow of rivers and streams. Recently, the National Green Tribunal has also issued a notice to the CIFRI on the depletion of fishery resources in various South Indian rivers like the Godavari.